

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज

भोपाल, शनिवार 21 से 27 जून 2025

भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित

वर्ष- 12

अंक-46

पृष्ठ- 8

मूल्य- रु. 5 /-

जैव ऊर्जा अगले 5 वर्षों में भारत के जीवाश्म ईंधन खपत का 50% हिस्सा कवर कर सकती है: नितिन गडकरी

भोपाल: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जैव ऊर्जा अगले पांच वर्षों में भारत की जीवाश्म ईंधन खपत का 50% हिस्सा कवर कर सकती है। यह बयान देश के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव और आत्मनिर्भरता की ओर इशारा करता है।

जैव ऊर्जा: टिकाऊ विकल्प

जैव ऊर्जा, जो कृषि अवशेष, जैविक कचरे और बायोमास से बनती है, स्वच्छ और नवीकरणीय है। गडकरी ने बताया कि भारत में बायोमास की प्रचुरता के कारण इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

भारत में संभावनाएं

भारत में हर साल लाखों टन कृषि अवशेष और जैविक कचरा उत्पन्न होता है, जिससे बायोएथनॉल, बायोगैस और बायो-सीएनजी बनाया जा सकता है। गडकरी ने कहा कि बायोएथनॉल और बायो-सीएनजी से परिवहन क्षेत्र में ईंधन खपत कम होगी, जिससे आयात निर्भरता घटेगी और किसानों को अतिरिक्त आय होगी।

सरकार की पहल

सरकार ने जैव ईंधन नीति को मजबूत किया है, जिसमें बायोएथनॉल और बायोडीजल उत्पादन के लिए सब्सिडी दी जा रही है। बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिल रहा है। पराली जलाने की समस्या को बायोमास के उपयोग से हल किया जा सकता है, जिससे प्रदूषण कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को लाभ

जैव ऊर्जा से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। यह छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित कर स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान देगा।

चुनौतियां और समाधान

जैव ऊर्जा को लागू करने में तकनीकी बुनियादी ढांचे, जागरूकता और निवेश की चुनौतियां हैं। सरकार इनका समाधान करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही है।

**निष्कर्ष**

गडकरी का बयान भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए सकारात्मक है। जैव ऊर्जा से ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, पर्यावरण बचेगा और आर्थिक विकास होगा। पांच वर्षों में जीवाश्म ईंधन खपत को 50% कम करने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी, लेकिन सरकार और जनता के सहयोग से संभव है।

Source: Economics Times

रिलायंस इंफ्रा की सहायक कंपनी ने डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर भारत में फाल्कन 2000 के निर्माण की शुरुआत की; पहली डिलीवरी 2028 में अपेक्षित

भोपाल: रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी, रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड (RAL), ने फ्रांस की अग्रणी एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट्स के निर्माण की घोषणा की है। यह साझेदारी भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि यह पहली बार होगा जब डसॉल्ट अपने फाल्कन 2000 विमान की असेंबली फ्रांस के बाहर करेगा।

साझेदारी का विवरण

पेरिस एयर शो में की गई इस घोषणा के अनुसार, नागपुर, महाराष्ट्र में डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड (DRAL) में एक अत्याधुनिक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी। यह सुविधा फाल्कन सीरीज के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र (CoE) के रूप में विकसित होगी, जिसमें फाल्कन 6X और फाल्कन 8X के भविष्य के असेंबली प्रोग्राम भी शामिल होंगे। पहला 'मेड इन इंडिया' फाल्कन 2000 विमान 2028 तक कॉर्पोरेट और सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार होगा।

उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण

इस समझौते के तहत, डसॉल्ट एविएशन फाल्कन 2000 के पूरे फ्यूजलेज और विंग्स की असेंबली, साथ ही फाल्कन 8X और फाल्कन 6X के फ्रंट सेक्शन की असेंबली को DRAL में स्थानांतरित करेगा। नागपुर संयंत्र में बड़े पैमाने पर सुविधा उन्नयन किए जा रहे हैं, जो

2028 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह कदम भारत को वैश्विक एयरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला में एक रणनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

आर्थिक और शेयर बाजार प्रभाव

घोषणा के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 5% की तेजी दर्ज की गई। यह साझेदारी न केवल भारत के एयरोस्पेस उद्योग को बल देगी, बल्कि निर्यात क्षमता को भी बढ़ाएगी। डीआरएएल अगले दशक में सैकड़ों इंजीनियरों और तकनीशियनों की भर्ती करेगा, जिससे उच्च-कौशल रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

नेतृत्व की प्रतिक्रिया

रिलायंस ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष अनिल डी. अंबानी ने कहा, "यह साझेदारी रिलायंस ग्रुप के लिए एक मील का पत्थर है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' के दृष्टिकोण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 'मेड इन इंडिया' फाल्कन 2000 भारत की तकनीकी और विनिर्माण क्षमता का प्रतीक होगा।"

डसॉल्ट एविएशन के अध्यक्ष और सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा, "यह समझौता हमारी 'मेक इन इंडिया' प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और भारत को वैश्विक एयरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख साझेदार बनाने की हमारी इच्छा को दर्शाता है।"

**डीआरएएल की पृष्ठभूमि**

2017 में स्थापित डीआरएएल ने 2019 में अपने पहले फाल्कन 2000 फ्रंट सेक्शन की डिलीवरी के बाद से 100 से अधिक प्रमुख उप-खंडों का निर्माण किया है। यह भारत की सटीक विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। यह साझेदारी भारत को अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों के विशेष समूह में शामिल करती है, जो वैश्विक बाजारों के लिए बिजनेस जेट्स का निर्माण करते हैं।

निष्कर्ष

यह साझेदारी भारत के एयरोस्पेस उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। 'मेड इन इंडिया' फाल्कन 2000 का पहला विमान 2028 में उड़ान भरेगा, जो भारत की विनिर्माण शक्ति का प्रतीक होगा।

Source: Business Standard

जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने भारत में लॉन्च किया 'अलादीन' निवेश प्रबंधन प्लेटफॉर्म

भोपाल: जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JFSL) और विश्व की अग्रणी निवेश कंपनी ब्लैकरॉक के 50:50 संयुक्त उद्यम, जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने भारत में ब्लैकरॉक के अनूठे निवेश विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन प्लेटफॉर्म 'अलादीन' को लॉन्च किया है। यह घोषणा मई 2025 में सेबी से परिसंपत्ति प्रबंधन लाइसेंस प्राप्त होने के एक महीने बाद की गई है। यह पहली बार है जब अलादीन, जिसका पूरा नाम 'एसेट, लायबिलिटी, डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क' है, भारतीय निवेशकों के लिए उपलब्ध हुआ है।

जियो ब्लैकरॉक ने एक बयान में कहा, "निवेश को सरल और निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। यही विश्वास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक को एक साथ लाया। हमने जियो के डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण को ब्लैकरॉक की वैश्विक निवेश विशेषज्ञता के साथ मिलाकर भारतीय निवेशकों के लिए समाधान तैयार किए हैं।" अलादीन एक व्यापक मंच है जो जोखिम विश्लेषण, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ट्रेडिंग और संचालन को एकीकृत करता है। यह विश्व स्तर पर 200 से अधिक वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाता है और \$21 ट्रिलियन से अधिक की संपत्तियों का प्रबंधन करता है।

यह मंच भारतीय निवेशकों को वैश्विक स्तर की पोर्टफोलियो रणनीतियाँ

तैयार करने, निवेशों की निगरानी करने और बाजार के उतार-चढ़ाव का आकलन करने में मदद करेगा। विशेष रूप से, यह डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण के साथ खुदरा और संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश को अधिक पारदर्शी और किफायती बनाएगा। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने कहा, "यह केवल शुरुआत है। हम निवेश को सुलभ और किफायती बनाकर भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

"अलादीन के साथ, हम वॉल स्ट्रीट की तकनीक को भारतीय निवेशकों के लिए ला रहे हैं।" – जियो ब्लैकरॉक प्रवक्ता

29 अक्टूबर 2024 को, कंपनी ने जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जियो ब्लैकरॉक ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के गठन की घोषणा की थी। इसके अलावा, 10 जून 2025 को सेबी ने जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया।

भारत में म्यूचुअल फंड और धन प्रबंधन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें डीमैट खातों की संख्या और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों की वृद्धि शामिल है। जियो ब्लैकरॉक का अलादीन लॉन्च इस क्षेत्र में तकनीकी



नवाचार को बढ़ावा देगा, जिससे निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

"जियो और ब्लैकरॉक का यह गठजोड़ भारत के निवेश भविष्य को नया आकार देगा।" – वित्तीय विश्लेषक

Source: Business Standard

INVESTMENT AVENUES®

Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In Bhopal

Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.

Secure Deals. Smart Investments.



EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586



Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor



Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor



Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

The World's 3rd Largest Economy – A New Dawn for Women

By Alpa Shah, Author of "Every Woman Should Invest" & "The Business Women" | Financial Literacy Advocate | Founder, Empower Education and Managing Trustee, Freedom Foundation

India's recent rise to the world's third-largest economy is more than just a GDP milestone; it is also a beacon of hope, opportunity, and transformation for millions of people, particularly women.

As we celebrate this economic win, we must ask: How does this development translate into genuine change for India's women? The answer is both promising and powerful.

1. More Jobs, More Inclusion

An expanding economy means more jobs in manufacturing, services, technology, finance, and entrepreneurship. These are no longer male strongholds. Today, startups, corporations, and government-backed initiatives are all actively working to expand women's job participation.

Women are joining, leading, and creating the future in industries ranging from Tirupur garment clusters to Bangalore fintech enterprises. Programs such as Skill India, Digital India, and Make in India are becoming more gender-sensitive, providing training and employment opportunities for people with a variety of abilities and backgrounds.

2. Financial Independence Through Entrepreneurship

India's rising economy has resulted in a healthy ecosystem of loans, mentoring, and market access for female entrepreneurs. Stand-Up India, Mudra Loans, and the Mahila Coir Yojana all aim to empower women to take responsibility.

I've witnessed it firsthand: women from tiny towns who once sewed blouses are now operating profitable online boutiques; homemakers are becoming digital resellers; and photographers, fashion designers, and agripreneurs are launching scalable businesses.

Economic expansion means that these success stories are no longer isolated; rather, they are multiplying.

3. Greater Access to Education and Digital Literacy

Prosperity generates budget surpluses, allowing governments to invest more in education and infrastructure. What was the result? Higher female literacy rates, improved school enrolment, and increased access to STEM education. With the digital revolution reaching rural India, women now have the ability to learn, earn, and lead from anywhere. Platforms that teach financial literacy, coding, digital marketing, and even cryptocurrency trading are encouraging women to dream big and act boldly.

4. A Booming Financial Market: Women as Investors

Being a part of a rising economy entails increased awareness and access to financial instruments. Women today are not merely saving in gold or fixed deposits. They invest in mutual funds, SIPs, equities, and even real estate investment trusts.

We must change our thinking from "mere bachana hai" to "bhavishya banana hai." Systematic Investment Plans (SIPs), Systematic Withdrawal Plans (SWPs), and Section 80C tax-saving mechanisms are now common topics in financial planning discussions among women's groups, families, and social media users.

5. Social Empowerment and Policy Push

An economically stronger India is better able to invest in social reforms and gender equality. We are witnessing a subtle but substantial shift in thinking, with stronger workplace harassment regulations, increased maternity benefits, and the promotion of women-friendly offices.

Furthermore, as more women take up leadership roles in politics, corporations, and communities, policies become more inclusive and responsive to real-world demands.

The Road Ahead: A Collective Responsibility

While we celebrate this economic triumph, we must guarantee that growth is equitable. A genuinely great nation is evaluated not only by GDP, but also by the empowerment of its women.

Let us ensure that every woman, whether urban or rural, paid or self-employed, educated or talented, has an equal opportunity to participate in and benefit from this economic boom.

Because when women rise, India not only grows, but also transforms.

"Every rupee a woman earns or invests is a seed for her family's progress and the nation's prosperity. Let's give her the tools, the trust, and the territory to bloom."

— Alpa Shah



I just turned 60 and already have close to
₹3 crore saved for retirement.

That's how wonderful SIP is...



If you are 30 or younger, **start by investing**

₹20,000/month
and you can build a corpus of

over ₹6 crore
by the time you retire.

*Assumed returns @12%

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the documents carefully before investing.

Vision Invest Tech Private Limited | (+91)7389912025
ARN-10613 | visionadvisorymkt@gmail.com

POWERED BY

wealthy

Hindustan Zinc Commits ₹12,000 Crore to Boost Production

Bhopal: Hindustan Zinc Limited, a Vedanta Group subsidiary and India's top zinc producer, has approved a ₹12,000 crore investment to double its production capacity, responding to India's growing zinc demand. The board sanctioned the first phase, which includes a new 250 KTPA integrated zinc smelter at Debari, Udaipur, alongside upgrades to mining and milling operations.

The 36-month project aims to enhance Hindustan Zinc's refined metal capacity, supporting India's infrastructure boom, projected to double zinc demand in 5–10 years, per the International Zinc Association. The initiative is part of the company's 2X growth plan to double zinc, lead, and silver output, solidifying its rank as the world's second-largest integrated zinc producer and third-largest silver producer.

CEO Arun Misra stated, "This expansion aligns with India's economic growth, ensuring self-reliance in zinc." With a market cap of ₹2.12 lakh crore, Hindustan Zinc leverages low-cost reserves and self-sufficient power to maintain global competitiveness. The share price dipped to an intraday low of ₹496.6, closing at ₹502.95, down 1.97%. Analysts attribute this to the stock trading ex-dividend after a ₹10 per share interim dividend (₹4,225 crore total) for FY 2025–26, with June 17 as the record date. Investors buying today missed the payout, triggering selling pressure. The BSE Metal Index, down 0.31%, and concerns over short-term project costs may have also contributed.

Despite the drop, Hindustan Zinc remains strong, posting a 47% net profit rise to



₹3,003 crore in the March 2025 quarter, with 20% revenue growth to ₹9,087 crore and a 53% EBITDA margin. Its ₹12,250 crore FY24 dividend payout underscores its shareholder focus.

The company plans to double silver production to 1,500–2,000 tonnes and build a fertilizer plant in Rajasthan, enhancing its market position. While the market's reaction seems tied to the ex-dividend date, Hindustan Zinc's long-term outlook remains robust as it executes its growth strategy amid rising domestic and global demand.

Sources: News18

मारुति सुजुकी ने मानेसर टर्मिनल के साथ FY31 तक 35% वाहन डिस्पैच रेलवे के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा

भोपाल: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े इन-प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया, जिसके जरिए वित्त वर्ष 2031 तक अपने 35% वाहनों को रेलवे के माध्यम से डिस्पैच करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत में भी कमी आएगी।

परियोजना का विवरण

इस मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल पर 452 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने बताया कि यह टर्मिनल प्रतिवर्ष 4.5 लाख कारों को भेजने की क्षमता रखता है। मारुति ने वित्त वर्ष 2025 में अब तक 5.18 लाख वाहनों को रेलवे के जरिए डिस्पैच किया है, जो कुल डिस्पैच का 25% है। यह टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा।

पर्यावरणीय प्रभाव

यह परियोजना सड़क परिवहन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। कंपनी के अनुसार, रेलवे के उपयोग से अब तक 1.8 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी और 630 लाख लीटर ईंधन की बचत हुई है। मारुति सुजुकी ने FY15 के बाद से रेलवे के उपयोग को आठ गुना बढ़ाया है, और यह नया टर्मिनल इस प्रक्रिया को और तेज करेगा। यह कदम टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

कंपनी का दृष्टिकोण

मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक ताकेउची ने कहा, "यह पहल 'मेक इन इंडिया' और 'गति शक्ति' जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ तालमेल रखती है। हमारा लक्ष्य टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।" इस परियोजना से स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

चुनौतियां और आलोचनाएं

विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे परिवहन से सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। हालांकि, कुछ पर्यावरणविदों ने रेलवे लाइनों के विस्तार से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव की चिंता जताई है। मारुति ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

Source: Economics Times



Stuck with the wrong
Health insurance policy?

 **Solution**

Port your policy



Why port your health insurance?

Continue with your
existing waiting
periods, no need to
start over

Keep your valuable
No Claim Bonus
(NCB) intact

You may pay a
lower premium

Experience better
service from your
new insurer

**I can help you choose a health insurance policy
that is best for you!**

Jio Financial Services Secures Full Ownership of Jio Payments Bank with Rs 104.5 Crore Acquisition from SBI

Bhopal: Jio Financial Services Ltd (JFS), a leading non-banking financial company under the Reliance Industries umbrella, has acquired the remaining 17.83% stake in Jio Payments Bank Limited (JPBL) from the State Bank of India (SBI) for Rs 104.54 crore. This strategic move, completed on June 18, 2025, following regulatory approval from the Reserve Bank of India (RBI) on June 4, 2025, transforms Jio Payments Bank into a wholly-owned subsidiary of JFS.

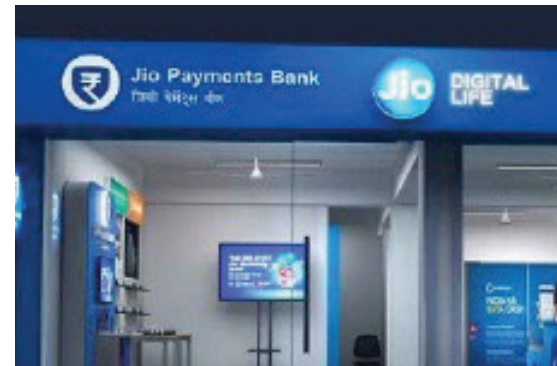
Jio Financial Services, which previously held an 82.17% stake in the payments bank, purchased 7.91 crore equity shares from SBI at Rs 13.22 per share. The acquisition, valued at approximately Rs 586 crore for the bank's total equity, marks a significant step in JFS's strategy to bolster its digital financial services ecosystem. The deal was finalized within 45 days of RBI approval, as stipulated in the initial announcement made on March 4, 2025.

Jio Payments Bank, established in April 2018 as a joint venture between Reliance Industries and SBI, has grown to serve 1.89 million Current Account Savings Account (CASA) customers as of December 2024. Operating under India's payments bank framework, it facilitates deposits up to Rs 2 lakh per customer and provides services such as UPI payments, savings accounts, and digital

financial solutions, though it is restricted from lending activities. The acquisition has been met with positive market sentiment, with JFS shares closing at Rs 206.35 on March 4, 2025, up 2.69% from the previous day's close, and reaching an intraday high of Rs 208 on the BSE. By June 17, 2025, the stock was trading at Rs 290, reflecting a market capitalization of Rs 1.84 lakh crore. Analysts view this move as a strengthening of JFS's position in India's competitive fintech and digital payments sector, aligning with its broader financial services portfolio, which includes lending, insurance broking, and payment gateway services.

"This acquisition is a pivotal moment for Jio Financial Services as we deepen our commitment to transforming digital banking in India," said Hitesh Kumar Sethia, Chairman and Managing Director of JFS. "With full ownership of Jio Payments Bank, we are better positioned to innovate and expand our offerings to meet the evolving needs of our customers."

The transaction, clarified as not being a related-party deal, involves no financial interest from JFS promoters or group entities beyond the agreed terms. JFS's recent financial performance underscores its growth trajectory, with a consolidated net profit of Rs 316.11 crore for the March 2025 quarter, up 1.76%



year-on-year, and assets under management rising to Rs 4,199 crore by December 2024.

Industry observers note that this acquisition enhances JFS's digital footprint, which already boasts 7.4 million monthly active users across its platforms, including the JioFinance app launched in May 2024. The company's partnerships, such as its joint venture with BlackRock for wealth management and broking services, further signal its ambition to dominate India's financial services landscape.

As Jio Payments Bank integrates fully under JFS, the move is expected to streamline operations and accelerate innovation in digital payments, positioning JFS as a formidable player in India's rapidly evolving fintech ecosystem.

Sources: Business Today

Welocity 2025: Wealthy ने एमएफ लीडर्स व डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारत की

बेंगलुरु, 20 जून: भारत के प्रमुख म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म Wealthy.in ने शुक्रवार को अपना वार्षिक पार्टनर इवेंट वेलोसिटी 2025 आयोजित किया। इस आयोजन में Axis म्यूचुअल फंड, Tata म्यूचुअल फंड, Mirae Asset, Motilal Oswal, HDFC एमएफ, DSP और SBI म्यूचुअल फंड के सीईओ, सीआईओ और फंड मैनेजर जैसे दिग्गज शामिल हुए।

इस कार्यक्रम ने भारत की बढ़ती निवेश क्षमता और म्यूचुअल फंड्स की उसमें बढ़ती भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। वक्ताओं ने चर्चा की कि कैसे देश की आर्थिक प्रगति, डिजिटल बुनियादी ढांचा और बढ़ती वित्तीय जागरूकता म्यूचुअल फंड्स के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है।

मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ स्वरूप मोहंती ने निवेशकों के व्यवहार में आ रही पीढ़ीगत बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि युवा निवेशक जोखिम लेने को अधिक तैयार रहते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी अब भी सतर्क और आय-केंद्रित सोच रखती है।

टाटा म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राहुल सिंह ने कहा कि भारत को इस समय जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त है और इसे पूरी तरह उपयोग में लाना जरूरी है, इससे पहले कि देश की निर्भरता दर विकसित देशों की तरह होने लगे।

एसबीआई म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ सेल्स गौरव धर्माहा ने कहा कि चल रहा अमृत काल — जो आर्थिक परिवर्तन का निर्णायक दौर माना जा रहा है — म्यूचुअल फंड्स के लिए घरेलू बचत को उत्पादक निवेशों में बदलने का अनोखा अवसर है। वेलोसिटी 2025 ने भारत के म्यूचुअल फंड क्षेत्र की परिपक्वता और डिस्ट्रीब्यूटर्स व फंड हाउस के सहयोग की अहमियत को रेखांकित किया। बढ़ती निवेश जागरूकता और डिजिटल नवाचारों के चलते म्यूचुअल फंड्स अब आम भारतीय के लिए पहले से कहीं अधिक सुलभ होते जा रहे हैं।

फंड हाउस और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच सेतु का कार्य करने वाले प्लेटफॉर्म जैसे Wealthy.in आने वाले समय में सिर्फ म्यूचुअल फंड अपनाने को बढ़ावा नहीं देंगे, बल्कि लाखों भारतीयों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा की ओर भी मार्गदर्शन करेंगे।



Bitcoin's Big Bet: Are BlackRock and the U.S. Planning a Financial Revolution?

Introduction

The financial world is witnessing a paradigm shift as Bitcoin gains traction among major institutions like BlackRock and the U.S. government, traditionally reliant on gold as a safe-haven asset. This evolving dynamic raises questions about gold's future and the strategic intentions behind institutional Bitcoin adoption.

"Bitcoin is not just a currency; it's a revolution in how we perceive value." – Anonymous Crypto Analyst

Institutional Shift to Bitcoin

BlackRock, with over \$10 trillion in assets, has rapidly expanded its Bitcoin holdings through the iShares Bitcoin Trust (IBIT), which amassed nearly \$60 billion by November 2024, outpacing its gold ETF. The U.S. government is exploring a strategic Bitcoin reserve, with proposals like "The Bitcoin Act" indicating a move away from gold-centric policies. Posts on X highlight BlackRock's \$334.7 million Bitcoin purchase alongside firms like Fidelity, reflecting institutional confidence

in Bitcoin's decentralized, finite supply as an inflation hedge.

"The institutions are no longer watching from the sidelines; they're diving into Bitcoin headfirst." – Crypto Influencer on X
Bitcoin vs. Gold: A Changing Landscape
Bitcoin's rise challenges gold's \$17 trillion market cap, with BlackRock's CEO, Larry Fink, calling it a modern alternative due to its global accessibility. Despite Bitcoin's 6% price drop in early 2025, institutional backing remains strong. Gold, however, surged 16% amid economic uncertainty, suggesting its role as a tangible asset endures. A sharp gold price decline in the next 2-3 years seems unlikely, but Bitcoin's growth may limit gold's upside by diverting investment flows.

"Gold is the past, Bitcoin is the future, but both have a place in the present." – Financial Strategist

Strategic Implications

Speculation suggests BlackRock and the U.S. government are planning significant moves, such as integrating Bitcoin into

national reserves or financial systems. Discussions with sovereign wealth funds and state-level Bitcoin reserve initiatives hint at a redefinition of global finance, positioning Bitcoin as "digital gold" while gold retains traditional appeal.

Conclusion

The interplay between Bitcoin and gold will shape economic policies and investment strategies. Bitcoin's institutional embrace signals a transformative era, but gold's resilience ensures a balanced coexistence for now.

"In a world of uncertainty, Bitcoin and gold together hedge the future." – Investment Advisor

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor



Vodafone Idea की अमेरिकी साझेदारी से बाजार में नई उमंग

भोपाल:: Vodafone Idea (Vi) ने टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अमेरिका की AST Space Mobile के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जो स्मार्टफोन्स को सीधे सैटेलाइट के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान करने की तकनीक लेकर आई है। यह कदम भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला सकता है और कंपनी की वित्तीय सेहत को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है।

साझेदारी के पीछे की रणनीति

Vodafone Idea और AST Space Mobile की यह साझेदारी भारत के 212 मिलियन से अधिक वायरलेस ग्राहकों को सैटेलाइट-आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इस तकनीक से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जहां पारंपरिक टावरों की पहुंच सीमित है। यह कदम कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद कर सकता है।

बाजार की प्रतिक्रिया

इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया और बाजार में चर्चा जोरों पर है। निवेशकों को उम्मीद है कि यह साझेदारी Vodafone Idea के शेयरों में तेजी ला सकती है, जो पिछले कुछ समय से उतार-चढ़ाव का सामना कर रही थी। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी चुनौतियों और लागत का असर भी देखने को मिल सकता है। फिर भी, यह कदम कंपनी के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

AST Space Mobile का योगदान

AST Space Mobile एक अमेरिकी कंपनी है जो सैटेलाइट-आधारित मोबाइल नेटवर्क विकसित करने में माहिर है। इस साझेदारी से Vodafone Idea को उन्नत तकनीक का लाभ मिलेगा,

जो ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगी। कंपनी का दावा है कि यह सेवा स्टैंडर्ड स्मार्टफोन्स पर काम करेगी, जिससे अतिरिक्त हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

भविष्य की संभावनाएं

विश्लेषकों के अनुसार, यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा, तो भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी का नक्शा बदल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य और ई-कॉमर्स जैसे सेक्टरों को भी बढ़ावा मिलेगा। Vodafone Idea के लिए यह साझेदारी न केवल राजस्व बढ़ाने का मौका है, बल्कि कंपनी की छवि को भी नया आयाम दे सकती है।

निवेशकों के लिए सलाह

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस साझेदारी के परिणामों पर नजर रखें और निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। तकनीकी और नियामक मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस कदम का असली असर बाजार पर दिखेगा।

यह साझेदारी न केवल Vodafone Idea के लिए, बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक नई शुरुआत का संकेत देती है। आने वाले समय में इसके परिणामों पर सभी की नजर रहेगी।

Source: Mint

Property Exchange – Buy & Sell

1) 28000 sq feet on main road of suraj nagar near judicial academy Bhopal at very reasonable price .
Please call : Prakash 7389912007

2) Fully developed farm house of 55000 sq feet with construction swimming pool on Suraj nahar road Please call : Prakash 7389912007

3) 2.5 acre land near kerwa is on sale. Please call : Prakash 7389912007

4) Banglow at hill crist colony chuna bhatti. 1900 sq feet plot and 3500 sq feet construction. Added advantage of 3000 sq feet extra land .
Please call : Prakash 7389912007

एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज का IPO 24 जून से शुरू: ₹14,800 से करें निवेश

भोपाल: एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) 24 जून 2025 को निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। निवेशक इस इश्यू में 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कंपनी के शेयर 1 जुलाई 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे। यह IPO निवेशकों के लिए औद्योगिक और मेडिकल गैस सेक्टर में निवेश का एक आकर्षक अवसर लेकर आया है।

IPO के प्रमुख विवरण

एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज ने IPO के लिए प्राइस बैंड ₹380 से ₹400 प्रति शेयर तय किया है। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम लॉट साइज 37 शेयरों का है, जिसके लिए ₹400 के अपर प्राइस बैंड पर ₹14,800 का निवेश करना होगा। अधिकतम 13 लॉट यानी 481 शेयरों के लिए निवेशक ₹1,92,400 तक निवेश कर सकते हैं।

IPO का कुल आकार ₹852.53 करोड़ है, जिसमें ₹400 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 1,13,13,130 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। रिटेल निवेशकों के लिए 35%, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए 50%, और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए 15% हिस्सा आरक्षित है।

घटना	तारीख
आईपीओ खुलने की तारीख	24 जून, 2025
आईपीओ बंद होने की तारीख	26 जून, 2025
शेयर आवंटन की तारीख	30 जून, 2025
डीमैट में शेयर क्रेडिट	30 जून, 2025
लिस्टिंग की तारीख	1 जुलाई, 2025

कंपनी का व्यवसाय

एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज औद्योगिक, मेडिकल और स्पेशलिटी गैसेज का निर्माण और आपूर्ति करती है। कंपनी के उत्पादों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ड्राई आइस, मेडिकल ऑक्सीजन, LPG, और फायर फाइटिंग गैसेज शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी मेडिकल डिवाइसेज और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी का निर्यात कुछ पड़ोसी देशों में भी होता है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने ₹290.2 करोड़ का राजस्व और ₹45.29 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो 2023 के ₹223.71 करोड़ के राजस्व और ₹28.14 करोड़ के लाभ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025 के लिए, कंपनी ने ₹348.4 करोड़ का राजस्व और ₹83.3 करोड़ का शुद्ध लाभ reported किया है, जो इसके मजबूत विकास को दर्शाता है।

निवेश का उपयोग



IPO से प्राप्त फ्रेश इश्यू की राशि का उपयोग कंपनी अपने पूंजीगत व्यय, कर्ज चुकाने, और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। यह कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बाजार विस्तार में मदद करेगा।

विशेषज्ञों की राय

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज का IPO दीर्घकालिक निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है, क्योंकि कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत है और औद्योगिक गैस सेक्टर में मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे IPO में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करें।

आवेदन कैसे करें
निवेशक अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से ऑनलाइन या अपने ब्रोकर के जरिए इस IPO के लिए आवेदन कर सकते हैं। शेयरों का आवंटन 30 जून 2025 को होने की संभावना है, और डीमैट खातों में शेयर 30 जून को क्रेडिट किए जाएंगे।

यह IPO उन निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है जो मेडिकल और औद्योगिक गैस सेक्टर में निवेश की तलाश में हैं। अधिक जानकारी के लिए, निवेशक कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) को SEBI की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।

पतंजलि को मलेशियाई एजेंसी से 5 साल के सौदे के तहत 15 लाख पाम ऑयल बीज मिले

भोपाल: भारत की प्रमुख उपभोक्ता वस्तु कंपनी पतंजलि ग्रुप ने मलेशिया की सरकारी एजेंसी सावित किनाबालु ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस पांच साल के अनुबंध के तहत, सावित किनाबालु ने पतंजलि को 15 लाख पाम ऑयल बीज की आपूर्ति की है, जो 2027 तक चलेगी। यह कदम भारत में पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। पाम ऑयल, जो खाद्य तेलों और विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग होता है, भारत में बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक है, और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इस सौदे के जरिए पतंजलि का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देना है, जिससे आयात लागत कम हो और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले।

सावित किनाबालु ग्रुप, जो मलेशिया में पाम ऑयल उत्पादन में अग्रणी है, ने इस साझेदारी को दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग को मजबूत करने वाला कदम बताया। पतंजलि के प्रवक्ता ने कहा, “यह सौदा भारत में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देगा और हमें अपने उत्पादों के लिए स्थानीय स्रोतों पर निर्भर होने में मदद करेगा। हमारा लक्ष्य किसानों को सशक्त बनाना और सतत कृषि को बढ़ावा देना है।” पतंजलि ने पूर्वोत्तर भारत में एक पाम ऑयल मिल स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसके 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। यह सौदा भारत सरकार की उस पहल के अनुरूप है, जो पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स - ऑयल पाम (NMEO-OP) के तहत काम कर रही है।

हालांकि, इस खबर के बावजूद, पतंजलि के शेयर की कीमत में आज 2.14% की गिरावट देखी गई, जो बीएसई पर 1,813.60 रुपये तक पहुंच गई। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट समग्र बाजार भावना और खाद्य तेल क्षेत्र में मूल्य अस्थिरता के कारण हो सकती है, न कि इस सौदे के प्रत्यक्ष प्रभाव से। पतंजलि के पाम ऑयल खंड में दीर्घकालिक वृद्धि की संभावना मजबूत बनी हुई है, विशेष रूप से इसकी स्वयं की बागान से 70% पाम ऑयल प्राप्त करने की योजना को देखते हुए।

Source: Business Standard



WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj

Technical Head

anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1

- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	25112	25688	25411	25261	24984	24834	24557	24407
BANK NIFTY	56253	57531	56927	56590	55986	55649	55045	54706
FINNIFTY	26649	27228	26953	26801	26526	26374	26099	25947
MIDCAP	12984	13676	13426	13205	12955	12734	12484	12263
ACC	1822	1924	1900	1861	1837	1798	1774	1735
AXISBANK	1219	1264	1246	1232	1214	1200	1182	1168
ABCAPITAL	262	297	280	271	254	245	228	219
BHARTIARTL	1934	2075	2010	1972	1907	1869	1804	1766
BHEL	250	269	263	256	250	243	237	230
BIOCON	351	389	377	364	352	339	327	314
CDSL	1687	1831	1777	1732	1678	1633	1579	1534
DATAPATTERN	2960	3298	3204	3082	2990	2868	2776	2654
ESCORTS	3242	3508	3395	3318	3205	3128	3015	2938
EICHERMOTOR	5512	5833	5686	5599	5452	5365	5218	5131
FEDERAL BANK	207	218	214	210	206	202	198	194
GRINFRAPROJECT	1256	1404	1370	1313	1279	1222	1188	1131
HDFCBANK	1964	2035	2002	1983	1950	1931	1898	1879
HCLTECH	1737	1815	1780	1758	1723	1701	1666	1644
HINDUNILVR	2302	2380	2358	2330	2308	2280	2258	2230
HAL	4957	5396	5263	5110	4977	4824	4691	4538
HYUNDAI	1999	2214	2130	2064	1980	1914	1830	1764
IOC	139	148	145	142	139	136	133	130
ICICIBANK	1426	1465	1449	1437	1421	1409	1393	1381
INFY	1618	1690	1668	1643	1621	1596	1574	1549
ITC	417	426	423	420	417	414	411	408
KOTAKBNK	2164	2282	2229	2196	2143	2110	2057	2024
LICHOUSING	594	644	628	611	595	578	562	545
LT	3658	3783	3725	3691	3633	3599	3541	3507
LUPIN	1942	2090	2052	1997	1959	1904	1866	1811
MARUTI	12787	13499	13193	12990	12684	12481	12175	11972
M&M	3181	3466	3331	3255	3121	3046	2911	2836
MGL	1393	1538	1491	1442	1395	1346	1299	1250
MAZGAONDOC	3266	3642	3492	3379	3229	3116	2966	2853
PFC	408	445	430	419	404	393	378	367
RECLTD	394	428	416	405	393	382	370	359
RELIANCE	1464	1524	1496	1480	1452	1436	1408	1392
SBIN	795	819	809	802	792	785	775	768
SUNPHARMA	1663	1744	1717	1690	1663	1636	1609	1582
SHRIRAMFINANCE	664	714	697	680	664	647	631	614
TITAN	3510	3728	3636	3573	3481	3418	3326	3263
TCS	3429	3634	3586	3507	3459	3380	3332	3253
TATAMOTORS	676	751	732	704	685	657	638	610
UPL	632	675	664	648	637	621	610	594
VALIENT	416	506	488	452	434	398	380	344
WIPRO	266	278	272	269	263	260	254	251

Sula Vineyards Pioneers Fully Sustainable Winemaking to Combat Climate Challenges

In a bold move toward environmental responsibility, Sula Vineyards—India's largest and most celebrated wine producer—has announced its ambitious goal to achieve 100% sustainable winemaking. This initiative comes in response to the mounting pressures of climate change, which have begun to significantly affect viticulture across the globe, including India's key wine-producing regions.

Founded in 1999, Sula Vineyards has long been a pioneer in India's wine industry. Now, the company is setting new benchmarks by pledging to implement eco-friendly practices across its entire winemaking process—from vineyard to bottle. This includes reducing water usage, transitioning to solar energy, eliminating single-use plastics, and enhancing biodiversity in and around its vineyards.

"We believe sustainability is no longer a choice but a responsibility," said Rajeev Samant, Founder and CEO of Sula Vineyards. "With changing weather patterns and unpredictable rainfall, it's vital for us to adopt methods that protect both our wines and the environment."

Sula has already made considerable progress: over 60% of its electricity is sourced from solar panels, and the company recycles nearly 99% of its wastewater. By 2026, it aims to be fully powered by renewable energy and ensure that all packaging is biodegradable or recyclable.

The move not only strengthens Sula's environmental credentials but also aligns with growing consumer demand for eco-conscious products. As climate concerns reshape global agriculture, Sula's commitment sets a strong example for Indian agribusiness and the international wine community alike.

Source: Economics Times

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.